

## प्रकाशनार्थ

### पोषण पर पुनर्विचार

**पटना, 29 जनवरी।** आज आइजीसी (इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर) और आद्री द्वारा 'पोषण पर पुनर्विचार' शीर्षक वेबिनार का आयोजन किया गया। पैनल का संचालन लंदन स्कूल ऑफ हाइजिन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन की सुनीता कादियाला ने किया। पैनल में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रांची विश्वविद्यालय के ज्यां ट्रेज, एकजुट के प्रशांत त्रिपाठी, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूर्णिमा मेनन ने भागीदारी की।

बच्चों के पोषण के संबंध में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं और कुपोषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों तथा भोजन से संबंधित राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा हाल में जारी किए गए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों ने भारत में कुपोषण पर बढ़ती चिंता को दर्शाया है। साथ ही, वैश्विक भूख सूचकांक (2020) में भारत 107 देशों के बीच 94वें स्थान पर है।

**प्रशांत त्रिपाठी** ने राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर बोलते हुए डॉ. पूर्णिमा मेनन के ब्लॉग को उद्धृत किया और कहा कि यह आग लगने की चेतावनी जैसा है, और यह आग कई स्रोतों से आ रही है। उन्होंने वितरण संबंधी पहलू को रेखांकित किया जो यह समझने के लिए जरूरी है कि किसको लाभ हुआ और किसको नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पलनाघर, गृहभ्रमण, और परामर्श पर फोकस के परिणाम दिखे हैं। उन्होंने कुपोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों की जरूरत बतलाई।

**ज्यां ट्रेज** ने कहा कि 2015-16 में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के चक्र में बजट में कटौती का प्रभाव बच्चों के कार्यक्रम पर पड़ा है। इसने सेवा प्रदान और स्टाफ के वेतन पर प्रभाव डाला है। और पोषण अभियान तो समुद्र में एक बूंद की तरह है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें चावल और गेहूं पर अधिक ध्यान देने से हटकर दाल को जन वितरण प्रणाली में शामिल करने की जरूरत है जो कोविड-19 जनित लॉकडाउन के दौरान किया गया था। अगर हम जन वितरण प्रणाली में विविधीकरण करके अन्य खाद्यान्नों को भी शामिल करना आगे भी जारी रखें तो अच्छी बात होगी। मध्याह्न भोजन में अंडों का प्रावधान किया गया है जो अनेक राज्यों में बच्चों को अभी भी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि तथ्य के रूप में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय नीति में अंडों को शामिल करना बच्चों के लिए लाभप्रद होगा।

**अर्जन दे वगत** ने कहा कि ठिगनापन को समझने के लिए मौसमीपन एक बड़ा कारक है - अनेक अन्य कारकों, जैसे कि डायरिया, संभवतः रक्ताल्पता, संभवतः

कम वजन आदि अन्य सूचकों के लिए भी मौसमीपन को समझना होगा। आंकड़ों से चिपके नहीं रहें। बड़े फलक में सोचें। बच्चों की स्थिति के बारे में ढेर सारे आंकड़े मौजूद हैं और इस बारे में भी कि अलग-अलग कार्यक्रमों की पहुंच हो रही है या नहीं। अब अप्रासंगिक विचारों पर दुबारा मंथन करने के बजाय जरूरी है कि सामूहिक रूप से कार्यक्रम की दुबारा पैकेजिंग करके वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन शुरू किया जाय। यह लीक पर डटे रहकर क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने और हर किसी तक पहुंचने का समय है क्योंकि यह महज 80 प्रतिशत तक पहुंचने की बात नहीं होकर शेष 20 प्रतिशत तक पहुंचने की बात है जिनको सबसे अधिक जरूरत है।

**पूर्णिमा मेनन** ने कहा कि जब हमने आंकड़ों पर नजर डाली तो बच्चों के पोषण में सुधार लाने के सारे मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की, ठिगनापन, कम वजन, रक्ताल्पता, दुबलापन पर अलग-अलग नहीं। उसके बाद हमने उन परिणामों के वाहकों का विश्लेषण करने की कोशिश की और हस्तक्षेपों को समझने का प्रयास किया जो परिणामों में सुधार के लिए इन वाहकों पर काम करते हैं। पोषण के वित्तपोषण पर उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट का विश्लेषण पोषण-आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, लेकिन यह दायरे का विस्तार करने का समय है क्योंकि बच्चे परिवारों में बढ़ते हैं और हमें पूरे परिवार को देखना चाहिए। किसी बाल हितैषी बजट में बच्चे के माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

**सुनीता कादियाला** ने कहा कि कहा जाता है कि बच्चे को पालने में पूरा गांव लगता है। इसलिए बच्चों पर अगले बजट के लिए और पोषण में सुधार के लिए हमें इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए।

आद्री की डॉ. अस्मिता गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)